

19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

- बिजली गिरने के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट
- खराब मौसम को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क

नई दिल्ली, 16 मई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में 16 मई को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है.

कई इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना



है. इसके साथ ही, उत्तर भारतीय राज्यों में एक बार फिर भयंकर तूफान आ सकते हैं, जबकि कई इलाकों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है.

पंजाब के छह जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. चंडीगढ़ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, अमृतसर,

होशियारपुर और मुक्तसर में बिजली कड़कने के साथ भयंकर आंधी-तूफान की संभावना है. इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 16 मई से 20 मई तक पंजाब के कई हिस्सों में लू की स्थिति के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

मौसम विभाग ने देश के 19 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और अंडमान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की चेतावनी दी है. दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान आसमान आम तौर पर साफ रहा. मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि मानसून आज दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व हिस्सों, अंडमान सागर के अधिकांश क्षेत्रों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह और विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया है.

आज का इतिहास

- 1769- ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए
- 1857- बहादुर शाह जफर द्वितीय को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित किया गया
- 1949- भारत ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह में बने रहने का फैसला किया
- 1951- प्रसिद्ध भारतीय गजाल और पार्श्वगायक पंकज उदास का जन्म
- 1953- हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म
- 1972- पद्म श्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के का निधन
- 1974- आयरलैंड के डबलिन शहर में तीन कार बम धमाकों में 23 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हुए
- 1975- जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबैई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी



राजगीर, बिहार में सज-धज कर तैयार हो गया है राजगीर का कुंड इस क्षेत्र में आज से शुरू हो गया है ऐतिहासिक मेलामास मेला.

ब्रिटेन में भारतीय मूल इमाम को उग्रकैद

नई दिल्ली, 16 मई. पूर्वी लंदन में एक भारतीय मूल के इमाम को उग्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसने धार्मिक नेता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला श्रद्धालुओं का यौन शोषण किया था. अब्दुल हलीम खान को गुरुवार को स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई. उसे 2004 से 2015 के बीच सात महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किए गए 21 यौन अपराधों का दोषी पाया गया था. जस्टिस लेस्ली कथबर्ट ने आदेश दिया कि 54 वर्षीय खान को पैरोल के लिए पहले कम से कम 20 साल की सजा काटनी होगी. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि खान ने आध्यात्मिक शक्तियां होने का झूठा दावा किया था और इन दावों का इस्तेमाल 12 साल तक की कम उम्र की लड़कियों को बहलाने-फुसलाने और यौन शोषण करने के लिए करता था.

जम्मू में 28 दिनों में 733 तस्कर गिरफ्तार

- 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस सरपेंड
- 180 आधार कार्ड डिएक्टिवेट किए गए

श्रीनगर, 16 मई. जम्मू और कश्मीर में पिछले 28 दिनों में ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े 733 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपी ड्रग पेडलर्स के 47 घरों पर बुलडोजर चलाया गया. अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए 373 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए और नियमों का उल्लंघन करने पर 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं.

दरअसल, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी खत्म करने के लिए 100



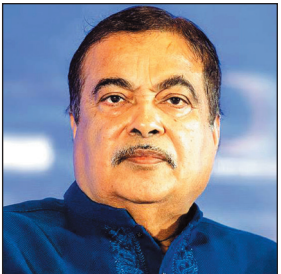
दिनों का अभियान शुरू किया था. तस्करों से जुड़े 180 आधार कार्ड डिएक्टिवेट (निष्क्रिय) कर दिए गए. इसके साथ ही सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे नशीली दवाओं से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी सामने आकर दें. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ में करीब 93 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की है. यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट

के तहत जम्मू के बाग-ए-बाहु थाना में दर्ज एक मामले से जुड़ी है. पुलिस के मुताबिक यह मामला 14 जनवरी 2026 का है. उस दिन जम्मू के नरवाल स्थित राजीव नगर निवासी अरुण सिंह को नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से 5.61 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जल संरक्षण के लिए जल संवाद जरूरी-गडकरी

नई दिल्ली, 16 मई. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण एवं भूजल संवर्द्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि इस दिशा में जनभागीदारी और जल संवाद बेहद जरूरी है तथा ड्रामों सभी को हिस्सा लेना चाहिए.

श्री गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार और सोमवार को आयोजित होने वाले जल संचयन एवं संरक्षण संबंधी जल क्रांति परिषद के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें विशेषज्ञ जल संरक्षण और भूजल संवर्द्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने लोगों, विशेषकर किसानों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के लिए विशेष



रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें जल संचयन और जल संरक्षण के प्रभावी उपायों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूजल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जलाशयों का निर्माण आवश्यक है. जल क्रांति परिषद लंबे समय से इस दिशा में कार्य कर रही है और उसका योगदान उल्लेखनीय है।श्री गडकरी ने कहा कि बुलढाणा जैसे कई क्षेत्रों में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं.

मैं नए सिरे से पार्टी शुरू करूंगी : ममता बनर्जी

- ममता बोर्ली- जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहता है जाए
- पार्टी को फिर खड़ा करने की अपील

कोलकाता, 16 मई. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी नेताओं को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है. सत्ता से बाहर होने की के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं को साफ संदेश देते हुए कहा कि जो लोग टीएमसी छोड़ना



चाहते हैं, वे बिना दबाव के जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं नए सिरे से पार्टी शुरू करूंगी दरअसल हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद कई पार्टी नेताओं के बागी होने के खबरें आ रही थी.

दालमंडी में 6 मरिजदों को हटाने की डेडलाइन

- 226 साल पुरानी मस्जिद पर भी खतरा

वाराणसी, 16 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे दालमंडी चौड़ीकरण अभियान ने अब नया मोड़ ले लिया है. प्रशासन की कार्रवाई अब उन धार्मिक स्थलों तक पहुंच गई है, जो दशकों से इलाके की पहचान माने जाते रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक दालमंडी क्षेत्र की छह मस्जिदें इस परियोजना की जद में आ गई हैं. इनमें से एक मस्जिद लगभग 226 साल पुरानी



मुस्लिम समुदाय में बढ़ी बेवैनी

मुस्लिम समुदाय और स्थानीय नागरिकों में इस फैसले को लेकर बेवैनी बढ़ रही है. लोगों का कहना है कि दालमंडी केवल बाजार नहीं, बल्कि वाराणसी की साझा सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है. यहां मौजूद मस्जिदें वर्षों से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही हैं. समुदाय के कई प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि चौड़ीकरण अनिवार्य है तो मस्जिदों को सम्मानपूर्वक दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हों.

ओबीसी प्रमाण पत्रों की दोबारा होगी जांच

- बंगाम के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को दिए निर्देश

कोलकाता, 16 मई. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पिछले 15 वर्षों के दौरान जारी किए गए सभी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है. पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विकास विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे वर्ष 2011 से 2026 तक जारी किए गए एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन करें.



यह अवधि पूर्व सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तीन कार्यकालों से जुड़ी हुई है. नबन्ना सचिवालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी

दस्तावेज देकर अवैध तरीके से ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र हासिल किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. इन 15 वर्षों में राज्य में कुल करीब 1.69 करोड़ पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी किए गए.

- शुभेंदु अधिकारी को धमकी देने वाला गिरफ्तार

कोलकाता, 16 मई. भवानीपुर पुलिस स्टेशन को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की धमकी दी गई थी. अल-कायदा के नाम से ईमेल भेजने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. 14 मई को सुबह लगभग 10:15 बजे भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक ईमेल प्राप्त हुआ था. यह ईमेल मूल रूप से भवानीपुर पुलिस स्टेशन के कार्यवाहक की ईमेल आईडी पर आया था.

सिक्किम का स्नेह मेरी स्मृतियों में सदैव रहेगा

- राज्य स्थापना दिवस पर भावुक हुए पीएम मोदी

सिक्किम के प्रेम को पीएम ने सराहा

नई दिल्ली, 16 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिक्किम की आत्मीयता और वहां के लोगों का स्नेह उनकी यादों का अभिन्न हिस्सा बन गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे सभी बहनों



सिक्किम ने देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है : मोदी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं. कंचनजंगा की प्राकृतिक छटा, जैव विविधता से परिपूर्ण वातावरण और पूर्ण जैविक खेती वाले राज्य के रूप में सिक्किम ने देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. स्वच्छता, पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध सिक्किम देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. प्रदेश के निरंतर विकास, समृद्धि और सभी नागरिकों के सुख एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं.

और भाइयों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत के विकास में सिक्किम के योगदान का विशेष महत्व है। मैं राज्य के सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करता हूं.

दीक्षांत समारोह डॉ. पी.के. मिश्रा ने एनआईबीएम दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

डिजिटल भुगतान प्रणाली केवल एक तकनीक नहीं

नई दिल्ली, 16 मई. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डॉ. पी.के. मिश्रा ने आज पुणे, महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के 20वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया.

उन्होंने इस समारोह में शामिल होकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, 2024-26 बैच और स्वर्ण पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्नातक एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर में पेशेवर दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहाँ बैंकिंग का



दायरा महज सामान्य व्यापार से कहीं आगे तक फैला हुआ है. डॉ. मिश्रा ने कहा, दीक्षांत समारोह उपलब्धियों के पड़ाव होते हैं; लेकिन साथ ही ये बदलाव के क्षण भी होते हैं. डॉ. मिश्रा ने एक शीर्ष बैंकिंग थिंक-टैंक के रूप में एनआईबीएम की पाँच दशकों की विरासत पर विचार व्यक्त करते

हुए संस्थागत उत्कृष्टता के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जहाँ पारंपरिक बैंकिंग का ध्यान केवल बचत जुटाने पर था, वहीं आज के दौर में राष्ट्रीय अवसरों पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने स्नातक होने वाले छात्रों से आग्रह किया कि वे इस बदलते हुए दायरे को आत्मसात करें. उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में, आपको बैंकिंग और वित्त को कहीं अधिक व्यापक अर्थ समावेशन, अवसर, विश्वास और राष्ट्रीय विकास के रूप में देखना होगा. मिश्रा ने पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए समझाया कि

वित्त ने ऐतिहासिक रूप से पुष्टभूमि में रहकर एक मूक सहायक की भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्त के बीच के संबंधों को ठीक से समझा नहीं गया, जिसके कारण अक्सर कम सुविधा प्राप्त वर्ग औपचारिक संस्थागत सहयोग से वंचित रह गया. उन्होंने दोहराया कि ऋण की उपलब्धता में यह असंतुलन लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. उन्होंने कहा, 'ऋण आर्थिक कार्यों, आजीविका सृजन और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है.

182 करोड़ की जिहादी ड्रग कैप्टान जल

नई दिल्ली 16 मई. नारकोटिक्स फट्रोल ब्यूरो ने अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑपरेशन रेजपिल के तहत जिहादी ड्रग कैप्टान की तस्करी में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 227.7 किलो कैप्टान जल की है जिसकी बाजार में कीमत 182 करोड़ रुपये है।यह पहला मौका है जब देश में इस तरह की खतरनाक ड्रग पकड़ी गयी है.इस मामले में सीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी.

सिंधु जल फैसले को भारत ने ठुकराया

- भारत बोला, न्यायाधिकरण का फैसला पूरी तरह अवैध

नयी दिल्ली 16 मई. भारत ने सिंधु जल संधि के संबंध में फैसला सुनाने वाले तथाकथित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवैध बताते हुए उसके फैसले को खारिज कर दिया है. भारत ने इस संबंध में अपने पहले के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा है कि उसने इस तथाकथित न्यायाधिकरण को कभी मान्यता नहीं दी है इसलिए इसके द्वारा सुनाये गये फैसले अवैध हैं. भारत ने जोर देकर कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थागित रखने का उसका निर्णय अभी भी



बरकरार है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस तथाकथित न्यायाधिकरण के फैसले से संबंधित मीडिया के प्रश्नों के जवाब में शनिवार को कहा कि अवैध रूप से गठित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 15 मई को एक फैसला दिया है, जिसे हमने सिंधु जल संधि के सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर पहले

जारी फैसले के पूरक के रूप में अधिकतम जलाशय से संबंधित बताया है. उन्होंने कहा, भारत तथाकथित फैसले को पूरी तरह खारिज करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण की सभी पूर्व घोषणाओं को दृढ़तापूर्वक खारिज किया है.